जुलाई 2024

₹ 20

समाजवादी बुलेटिन

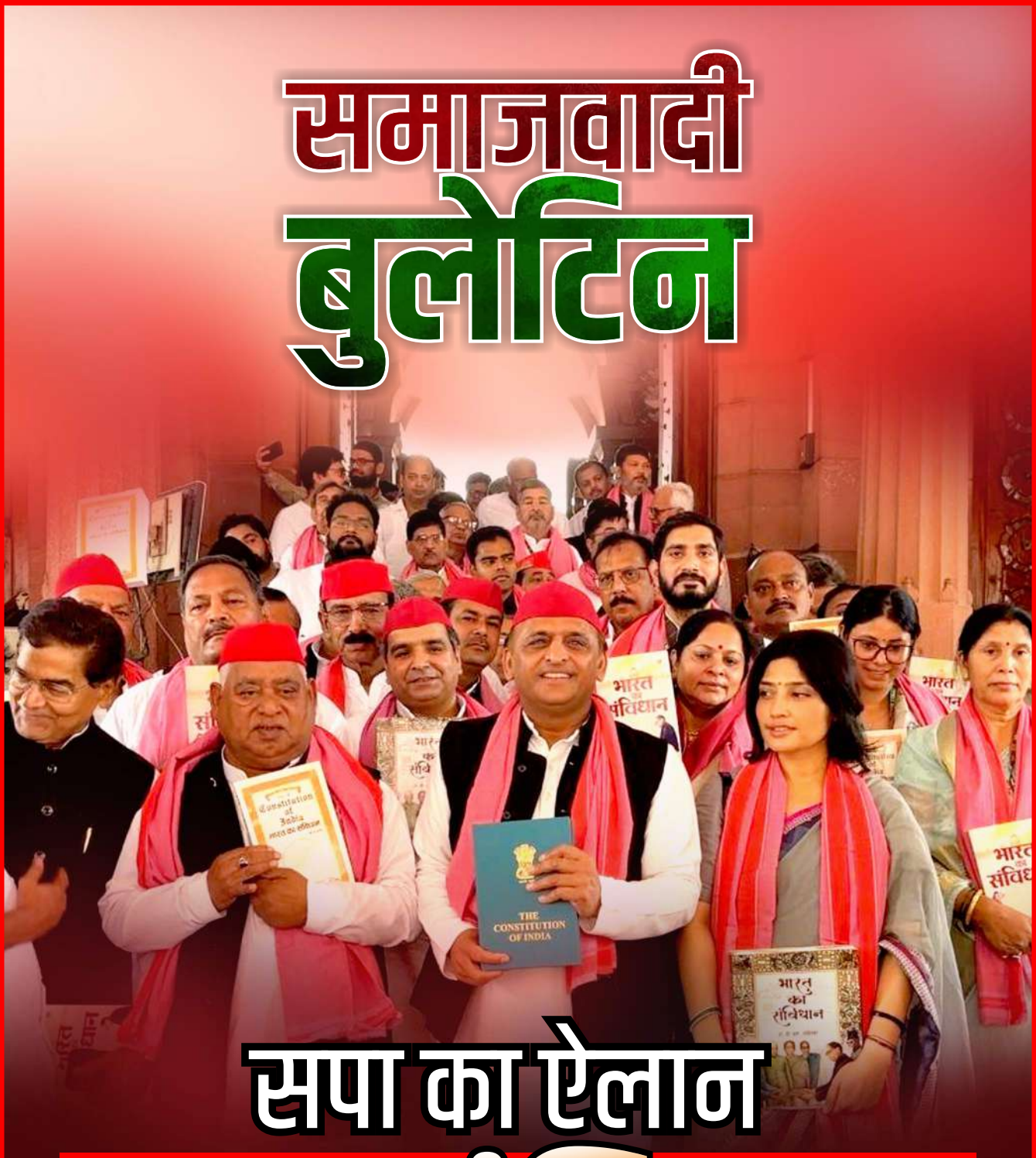

सपा का ऐलान

जय संविधान

R.N.I. No. 68832/97

समाजवादी पार्टी की नीति है किसानों को प्राथमिकता दी जाए। उन्हें सस्ते दामों पर खाद और बीज उपलब्ध कराया जाए। सिंचाई की उचित व्यवस्था हो ताकि पैदावार बढ़े। फसलों को उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित हो। इसी तरह नौजवानों के लिए नौकरी का इंतजाम किया जाना चाहिए। युवाओं को नौकरी व रोजगार देना केंद्र व प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकारों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

मुलायम सिंह यादव
संस्थापक, समाजवादी पार्टी

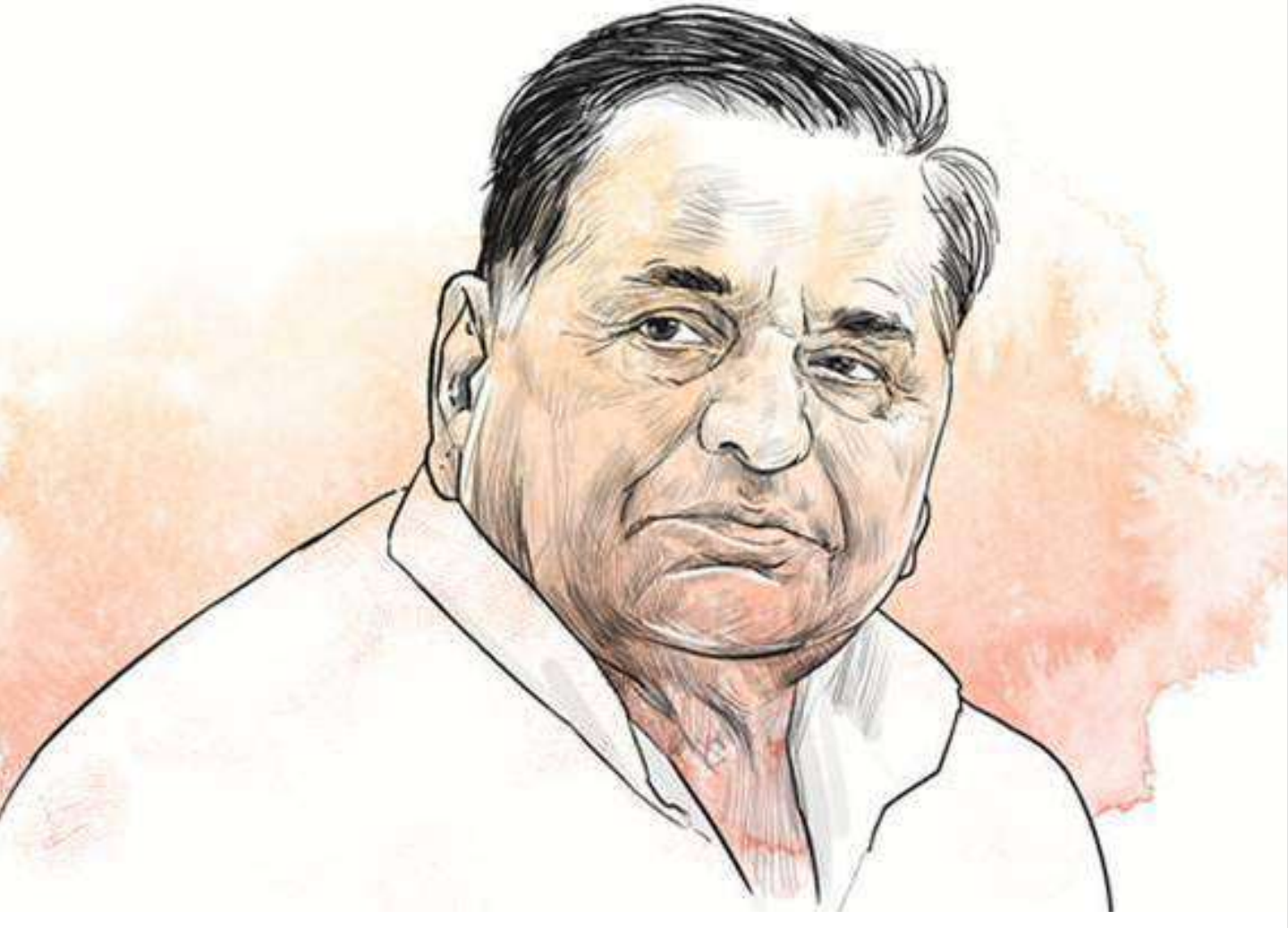

समाजवादी बुलेटिन

जुलाई 2024
वर्ष 25 | संख्या 09

प्रिय पाठकों,

आपको बधाई एवं हृदय तल से आभार। आपकी प्रिय पत्रिका समाजवादी बुलेटिन अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। आप सभी के प्यार और उत्साहवर्धन की बदौलत यह संभव हो पाया। समाजवादी बुलेटिन के ढाई दशक के सफर में इसके नए कलेवर को आपने खूब सराहा। हम भरोसा दिलाते हैं कि वैचारिक स्तर पर आपको समृद्ध करने का हमारा प्रयास सतत जारी रहेगा। कृपया अपना स्नेह यूं ही बनाए रखें।

धन्यवाद

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक

प्रोफेसर रामगोपाल यादव

☎ 0522 - 2235454
samajwadibulletin19@gmail.com
bulletinsamajwadi@gmail.com
Mob:- 9598909095
/samajwadiparty

समाजवादी पार्टी के लिए
19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित
अवध पब्लिशिंग हाउस, 8 पान दरीबा, लखनऊ से मुद्रित
R.N.I. No. 68832/97

कवर फोटो: (साभार /yadavakhilesh)

अंदर

PDA वृक्षारोपण अभियान: हरियाली बढ़ाने का संदेश 26

06 कवर स्टोरी

सपा का ऐलान
जय संविधान

युवाओं के हक में सड़क पर उतरे सपा कार्यकर्ता 32

नीट व दूसरी परीक्षाओं के लगातार पेपर लीक होने से परेशान छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए सपा लगातार मुखर है। युवाओं के अधिकारों के लिए पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। युवाओं के हक की आवाज को दबाने के लिए भाजपा सरकार कार्यकताओं के दमन पर उतर आई है लेकिन सपा कार्यकर्ता सड़क पर डटे हुए हैं।

सेकुलरिज्म और सोशलिज्म: संविधान की आत्मा 04

सपा के प्रति और बढ़ रहा है आकर्षण 42

सेकुलरिज्म और सोशलिज्म
संविधान की आत्मा

उदय प्रताप सिंह

26 जून 2024 को लोकसभा में स्पीकर के रूप में श्री ओम बिरला का चुनाव हुआ। सभी दलों के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। राहुल गांधी ने बधाई देते हुए अपेक्षा की कि इस बार अध्यक्ष जी प्रतिपक्ष के लोगों को भी निष्पक्ष होकर अपनी बात कहने का मौका देंगे ! लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की एक टिप्पणी ने सदन में तहलका मचा दिया।

उन्होंने कहा "माननीय अध्यक्ष जी आपके अध्यक्ष चुने जाने पर मैं आपको अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं और अंत में उन्होंने जो कहा वह अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि मैं अपेक्षा करता हूं कि सदन आपके इशारे पर चलेगा, कहीं इसका उल्टा नहीं होना चाहिए ! अखिलेश जी का साफ इशारा था कि 17 वीं लोकसभा में भी श्री बिरला जी स्पीकर थे और तब उनके समय में बहुत से ऐसे कार्य हुए जिससे पता चलता था कि यह उनका निर्णय नहीं है बल्कि किसी और के इशारे पर यह फैसला देने की व्यवस्था हुई। तब, सदन के 145 सदस्यों को एक साथ निष्कासित करना एक तरह से लोकतंत्र का उपहास था।

भारत का संविधान बहुत कुछ इंग्लैंड के अलिखित संवैधानिक परंपराओं पर आधारित है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ़ कॉमंस का स्पीकर चुने जाने के बाद सांसद अपने दल से संबंध विच्छेद कर लेता है और वह सब दलों और सदस्यों के स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षक हो जाता है।

इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमंस के स्पीकर और राजा के बीच संघर्ष की लंबी कहानी है। 1641 में चार्ल्स फर्स्ट ने हाउस ऑफ कॉमंस में आकर स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर स्पीकर को आदेश दिया कि वह हाउस ऑफ कॉमंस के उन 5 सदस्यों को जिनके ऊपर राजा ने मनमाने ढंग से आरोप लगा रखे थे, उन्हें राजा के हवाले कर दिया जाए। उस समय तत्कालीन स्पीकर विलियम लेंथल थे। तब उन्होंने कहा था कि श्रीमान मेरे पास न आंखें हैं न जुबान है और यह कहकर उन्होंने उन पांच हाउस ऑफ कॉमंस के सदस्यों को राजा के सुपुर्द करने से इनकार कर दिया था।

यहां यह भी स्मरणीय है कि इससे पहले 7 स्पीकरों को ऐसे ही विवादों के चलते राजाओं

ने अप्रसन्न होकर फांसी की सजा दे दी थी । इंग्लैंड में इस तरह हाउस ऑफ कॉमंस के सदस्यों व उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए स्पीकर्स ने संघर्ष किया है जिसका लंबा इतिहास है ।

भारत में भी लोकसभा के स्पीकर का इतिहास बहुत उज्ज्वल रहा है। अधिकांश लोकसभा के अध्यक्षों ने बिल्कुल निष्पक्षता और पारदर्शिता से सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में सहमति और संतुलन बनाए रखने का काम किया है। 1952 में पहली लोकसभा के चुनाव से पहले और संविधान लागू होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम संसद के अध्यक्ष के रूप में अकाली दल के सरदार हुकुम सिंह को नामित करते हुए कहा था कि जब तक अध्यक्ष विपक्ष का नहीं होगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। विडंबना यह है कि अध्यक्ष तो छोड़िए वर्तमान सरकार, विपक्ष का उपाध्यक्ष बनने को भी तैयार नहीं है।

18वीं लोकसभा का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है कि प्रारंभ से ही सत्ता पक्ष ने संघर्ष का रास्ता तैयार कर लिया। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में अपने पहले भाषण में इंदिरा गांधी के समय के आपातकाल का जिक्र किया और उसे इतिहास का काला पृष्ठ घोषित किया। ओम बिरला जी ने भी अध्यक्ष चुने जाने के बाद धन्यवाद भाषण में आपातकाल का जिक्र किया जो बिल्कुल अनावश्यक था।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्री ओम बिरला जी से व्यक्तिगत मुलाकात करके इस पर आपत्ति जाहिर की। हद तो तब हो गई जब महामहिम राष्ट्रपति ने भी आपातकाल का जिक्र किया। यह ठीक है कि ज्यादातर राष्ट्रपति को सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अपना प्रथम भाषण देना पड़ता है। पहले रहे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णनन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, क्या इन लोगों से ये उम्मीद की जा सकती थी कि वे सरकार द्वारा लिखे हुए शब्दों को ही पढ़ दें।

सेकुलरिज्म और सोशलिज्म संविधान की आत्मा है। वर्तमान सरकार ने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को अपने आचरण से बिल्कुल बाहर रखा है। वह इन दोनों धारणाओं में विश्वास ही नहीं करती। लोकतंत्र और संविधान को न मानना भी एक तरह से राजतंत्र की स्थापना का कदम है जो कि भविष्य के लिए आपातकाल से भी ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है

राष्ट्रपति को कोई ऐसी बात कहने से पहले सोचना चाहिए जिससे देश का अहित संभावित हो। अब बहस यह छिड़ गई है कि इंदिरा गांधी का घोषित आपातकाल और मोदी जी का अघोषित आपातकाल दोनों में कौन, देश के लिए अधिक अहितकर है। जिस तरह मोदी जी ने संविधान की अवहेलना करके लोकतंत्र की परंपराओं को नजरअंदाज करके अनेक काम किए हैं चाहे वह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को ध्वस्त करने का हो, स्वायत्तता प्राप्त संस्थाओं की स्वायत्तता समाप्त करके उन्हें अपनी कठपुतली बनाने का काम हो, चाहे बिना विपक्ष के परामर्श के नोटबंदी जैसे विवादग्रस्त फैसले लिए हों, एक नहीं बहुत से ऐसे मामले हैं।

सेकुलरिज्म और सोशलिज्म संविधान की आत्मा है। वर्तमान सरकार ने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को अपने आचरण से बिल्कुल बाहर रखा है। वह इन दोनों धारणाओं में विश्वास ही नहीं करती। लोकतंत्र और संविधान को न मानना भी एक तरह से राजतंत्र की स्थापना का कदम है जो कि भविष्य के लिए आपातकाल से भी ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे असंवैधानिक मामले उठाने का काम विपक्ष करना चाहेगा और यह स्पीकर का धर्म होगा कि वह लोकतंत्र के हित में उन मुद्दों को उठाने की अनुमति प्रतिपक्ष को दें। लोकसभा में अध्यक्ष, लोकतंत्र का संरक्षक होता है इसलिए उसे निष्पक्ष होकर पारदर्शिता से सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को बराबर एक नजर से देखना चाहिए, यही अध्यक्ष का बड़प्पन होता है।

आगे क्या होगा यह पता नहीं लेकिन यह निश्चित है कि इस विवाद के चलते संसद में जनता के असली मुद्दे गरीबी, बेरोजगारी, परीक्षाओं के पेपर लीक होना, अग्निवीर जैसे कई विवादित मुद्दों पर बहस करने का समय नहीं मिलेगा। ऐसा अधिकतर पत्रकार और विचारवान नागरिकों और जिम्मेदार लोगों को कहते मैंने सुना है इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने एक वाक्य में इशारा किया था कि सदन अध्यक्ष के इशारे पर चले इसका उल्टा न हो जाए कहीं...।

फोटो स्रोत : गूगल

सत्यमेव
जयते

सपा का ऐलान जय संविधान

बुलेटिन ब्यूरो

लोकसभा चुनाव-2024 की जब घोषणा हुई उस समय देश एक ऐसे दोराहे पर था जहां से राजनीति भाजपा को और ज्यादा ताकत देकर सत्ता में लाती या फिर देश की जनता विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA को समर्थन देकर राजनीतिक व्यवस्था में संतुलन लाती। असमंजस के दौर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने जनता के नाम अपील जारी की कि यह चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है।

श्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने उसके बाद अपने पूरे चुनावी अभियान को लोकतंत्र और संविधान बचाने के मुहिम के रूप में खड़ा कर दिया। उसका यह असर हुआ कि विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल बाकी दलों ने भी भाजपा को और ताकत मिलने पर संविधान ही खत्म हो जाने को बड़ा मुद्दा बनाया। समाजवादी पार्टी की पहल पर चले संविधान बचाओ मुहिम का जनता पर व्यापक असर हुआ और उसका ही नतीजा रहा कि चुनाव परिणाम में भाजपा की ताकत पहले से कहीं ज्यादा घट गई जबकि जनता ने INDIA गठबंधन की

ताकत बढ़ाकर भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की अहमियत को पुन: स्थापित किया।

लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी और राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी ने संविधान बचाने के अपने अभियान को 18वीं लोकसभा में भी कायम रखा है। कन्नाैज के सांसद के रूप में 1 8 वीं लोकसभा की पहली बैठक में पहुंचे श्री अखिलेश यादव ने अपने दल के बाकी सभी सदस्यों के साथ संविधान की प्रति हाथ में लेकर संसद भवन के अंदर प्रवेश किया। इतना ही नहीं सपा के सभी नव निर्वाचित लोकसभा सदस्यों ने अपनी शपथ भी संविधान की प्रति लेकर की।

लोकसभा में अपने संबोधन में भी श्री अखिलेश यादव व सपा के बाकी सांसदों ने संविधान की गरिमा बनाए रखने में कोई कसर न छोड़ने का खुले तौर पर ऐलान किया। संदेश साफ है कि समाजवादी पार्टी संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ अपने राजनीतिक अभियान को निरंतर जारी रखेगी।

उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय फलक तक यह और मजबूती से स्थापित हो चुका है कि श्री अखिलेश यादव की कथनी-करनी में कोई फर्क नहीं है। वह जो कहते हैं, करते जरूर हैं चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना हो मगर वह अपनी कथनी से कभी नहीं मुकरते। यही वजह है कि वह और नेताओं से अलग शुमार किए जाते हैं।

लोकसभा चुनाव-2024 में फिर उनकी इस छवि को और निखारा है। चुनाव से पहले ही उन्होंने संविधान की रक्षा का संकल्प लिया था और चुनाव प्रचार के दौरान भी इस पर अडिग रहे। यह श्री अखिलेश यादव की कथनी-करनी में फर्क न होने का ही परिणाम रहा कि जनता ने उन्हें यूपी का सिरमौर बना दिया क्योंकि जनता को यह अटूट विश्वास है कि श्री अखिलेश यादव अपनी जुबान पर कायम रहने वाले राजनेता हैं और किसी भी सूरत में संविधान की रक्षा जरूर करेंगे।

श्री अखिलेश यादव ने चुनाव बाद साबित कर दिया कि चुनाव प्रचार के दौरान कही गईं बातें या संकल्प जुमला नहीं हैं, वह हर हाल में संविधान को ही सर्वोपरि रखते हैं और संविधान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि देश संविधान से चलेगा और उसमें किसी तरह का बदलाव, सपा को नामंजूर है।

यह पहली बार नहीं हुआ है जब समाजवादी पार्टी ने संविधान की रक्षा का संकल्प लिया

फोटो स्रोत : गूगल

है। पहले भी समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी-मुलायम सिंह यादव इस मसले पर मुखर हो चुके हैं। 27 नवंबर 2015 को लोकसभा में नेताजी ने साफतौर पर कहा था कि अब लोग अपनी सुविधा के अनुसार संविधान बदल रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि क्या अब देश में डा अंबेडकर व डा राजेंद्र प्रसाद से ज्यादा काबिल लोग आ गए हैं। तब, उन्होंने इसी सदन में कहा था कि वह डा अंबेडकर के आभारी हैं जिन्होंने इतना बेहतरीन संविधान देश को दिया। यह वक्तव्य बताने के लिए काफी है कि संविधान को लेकर समाजवादी पार्टी हमेशा ही सजग रही है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव भी संविधान की रक्षा को लेकर हमेशा सचेत रहते हैं और अवाम को भी संविधान के बारे में सजग करते रहते हैं। भाजपा द्वारा संविधान बदले जाने की मंशा को भांपकर ही श्री अखिलेश ने जोर शोर से यह मसला उठाया था और देश की जनता ने भी भाजपा के इरादों को भांपकर श्री अखिलेश यादव का साथ दिया।

भाजपा की मंशा की शंका यूं ही नहीं पनपी बल्कि इसकी आहट पिछले कई साल से महसूस की जा रही थी। वह तो श्री अखिलेश यादव ने वक्त रहते संविधान बदले जाने के इरादों से जनता को जागरुक कर भाजपा की मंशा पर पानी फेर दिया वरना उसके इरादे का पता वर्ष 2000 में ही चल गया था जब उसने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मनेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया के नेतृत्व में एक संविधान समीक्षा आयोग गठित कर दिया था।

गनीमत रही कि वेंकटचलैया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संविधान के बुनियादी ढांचे में बदलाव की जरूरतें नहीं बताईं। उस वक्त भाजपा के मंसूबे धरे रह गए थे मगर उसने 2020 में फिर वही पुराना राग छेड़ा और इस बार नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के जरिये संविधान बदलने के लिए तर्क गढ़े। संविधान में बदलाव करने का मंसूबा लिए भाजपा शायद यह भूल गई थी कि समाजवादी पार्टी संविधान की रक्षा की सबसे बड़ी अलम्बरदार है और वह यह किसी सूरत में उसका मंसूबा पूरा नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट ऐलान है-जय संविधान। यह सही भी हैक्योंकि देश संविधान से चलेगा। संविधान से देश चलेगा तो पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों और समाज के दूसरे सभी तबकों को उनका हक मिलेगा। संविधान की जय इसलिए भी जरूरी है ताकि पिछड़ों-दलितों को आरक्षण मिलता रहे।

संविधान हाथ में अखिलेश साथ में

फोटो स्रोत : गूगल

बुलेटिन ब्यूरो

लोकसभा चुनाव-2024 में उत्तर प्रदेश से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के सभी 37 सांसद 24 जून को संविधान की प्रति हाथ में लेकर संसद भवन पहुंचे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के साथ संविधान की प्रति हाथ में लेकर पहुंचे सभी सांसद संसद भवन के मुख्य द्वार पर मीडिया से रूबरू हुए। संविधान की प्रति लेकर पहुंचे समाजवादी सांसद आकर्षण का केंद्र रहे और पूरे देश में यह संदेश गया कि संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी संकल्पित है।

लोकसभा चुनाव में शानदार जीत और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में संविधान की रक्षा का संकल्प लिया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने संविधान की रक्षा के लिए जनता को जागरुक किया जिसके नतीजे में जनता ने उनका भरपूर समर्थन किया।

18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हुआ। इससे पहले सपा के सभी सांसदों के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता श्री अखिलेश यादव ने बैठक की और उन्हें जनता की समस्याओं को संसद में उठाने के लिए प्रेरित किया। बैठक में रणनीति बनी कि जनता की समस्याओं से समाजवादी पार्टी को गाफिल नहीं होना है और किसी भी

कीमत पर संविधान की मर्यादा, गरिमा पर आंच नहीं आने देनी है।

24 जून को 18वीं लोकसभा की पहली बैठक वाले दिनों समाजवादी पार्टी के सभी सांसद एक साथ संसद भवन पहुंचे। सभी सांसदों के हाथ में संविधान की प्रति थी। जब समाजवादी पार्टी सांसदों का समूह संसद भवन पहुंचा तो मीडिया ने संविधान की प्रति लेकर पहुंचे सांसदों से ग्रुप फोटो का आग्रह किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के साथ सभी सांसदों की फोटो हुई।

संविधान की प्रति के साथ इस फोटो ने देशभर में सकारात्मक राजनीति की शुरुआत का व्यापक संदेश दिया। लाल टोपी में संविधान की किताब लेकर एक साथ मौजूद सांसदों के फोटो और इसका वीडियो खूब वायरल हुआ। बाद में समाजवादी पार्टी के सभी नव निर्वाचित लोकसभा सदस्यों ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर शपथ ग्रहण किया।

समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों ने एक स्वर में कहा है कि उनके साथ श्री अखिलेश यादव हैं और हाथ में संविधान की प्रति लिहाजा वे संसद में जन समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करेंगे और जनता के हितों के लिए लड़ते रहेंगे। नव निर्वाचित सांसदों का उत्साह बता रहा है कि वे संविधान बदलने की भाजपा की किसी भी मंशा का श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में संसद से सड़क तक जोरदार जवाब देंगे और संविधान में बदलाव के भाजपा के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे।

लोकसभा में अखिलेश ने सरकार को घेरा

बुलेटिन ब्यूरो

18वीं लोकसभा के पहले सत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता श्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा को विभिन्न मुद्दों पर जमकर घेरा। उन्होंने जनता के बुनियादी सवाल मजबूती से उठाए और सत्ताधारी भाजपा को साफ संदेश दिया कि जनता के सवालों पर समाजवादी पार्टी इसी तरह मुखर रहेगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में श्री अखिलेश यादव ने सारगर्भित भाषण देते हुए तमाम बुनियादी सवालों पर सरकार से जवाब मांगा। श्री अखिलेश यादव ने इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला को बधाई देते हुए उनसे अपेक्षा की कि उनका अंकुश सिर्फ विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष पर भी होगा। उन्होंने संसद के पुराने अनुभवों के हवाले से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार सदस्यों का निष्कासन नहीं होगा। उनकी इस अपील का सभी सदस्यों ने भी समर्थन किया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पहली बार लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है कि यह चलने वाली नहीं, गिरने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि वह चुने हुए साथियों को बधाई देते हैं, उन समझदार मतदाताओं को भी बधाई देते हैं जिन्होंने देश के लोकतंत्र को एकतंत्र बनाने से रोका।

बेबाकी से अपनी बात रखते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था मगर जनता ने हुकूमत का गुरूर तोड़ दिया है। उन्होंने इसपर एक शेर भी पढ़ा। श्री यादव ने एक अन्य शेर पढ़ते हुए कहा-

ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई

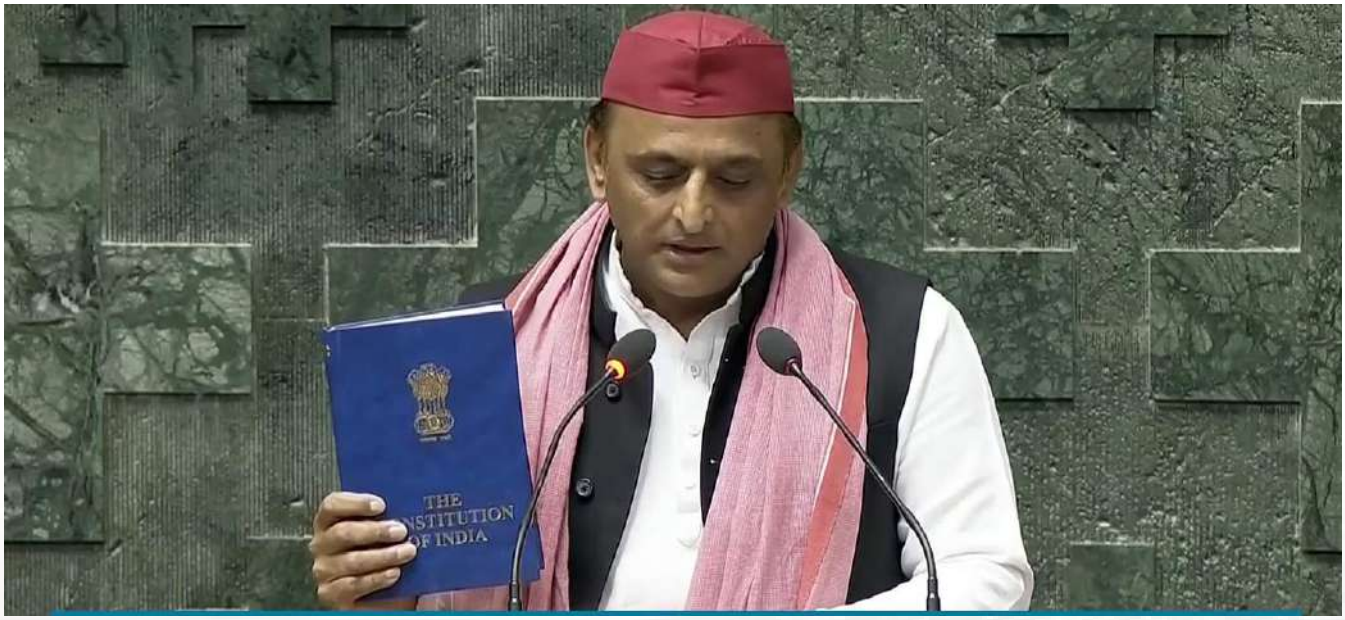

आधार नहीं

अधर में जो है अटकी हुई, वह तो कोई सरकार नहीं॥

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया की नैतिक जीत हुई। सकारात्मक राजनीति की जीत हुई। INDIA-PDA की सोशल जस्टिस की जीत हुई है। 2024 का चुनाव INDIA के लिए जिम्मेदारी से भरा पैगाम है।

उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 उपनिवेश से आजादी का दिन था तो इस बार 4 जून को सांप्रदायिक राजनीति का हमेशा के लिए अंत हुआ है। सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। छल, धन, बल, धर्म की राजनीति की शिकस्त हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम का पैगाम है कि देश मनमर्जी से नहीं, जनमर्जी से चलेगा। किसी की महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि देश जन आकांक्षाओं से चलेगा।

उन्होंने मां गंगा नदी की सफाई का जिक्र करते हुए कहा कि गंगा जल हाथ में लेकर कसमें खाई जाती हैं इसलिए उस गंगा मां से झूठ न बोला जाए। उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है। मामूली बारिश में ही सरकार की अव्यवस्था सामने आ गई है। यूपी में स्मार्ट सिटी का बुरा हाल है। बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं।

श्री यादव ने छुट्टा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि अनाथ पशुओं से छुटकारा दिलाने का वायदा किया गया था। कई चुनाव बीत गए मगर अभी तक निजात नहीं मिली। अब तो वचन देने वालों को भी याद नहीं है कि कहां वचन दिया था। उन्होंने कहा कि जितनी भी परीक्षाएं हुईं हैं, सभी के पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव हुआ है। प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया था, उसकी तस्वीर नहीं बदली।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया और नौकरी छीनी है। इस सरकार में न नौकरी की उम्मीद है और न रोजगार की। सरकार इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती है क्योंकि आरक्षण देना होगा। आरक्षण का हक हड़पा जा रहा है। अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए श्री यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर देगी।

श्री अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिना जातीय जनगणना के सभी को उनका हक नहीं मिल सकता। उन्होंने ईवीएम को हटाने के समाजवादी पार्टी के मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी यूपी में 80 में 80 सीटें भी जीत जाए तो भी समाजवादी लोग ईवीएम को हटाने के लिए अड़े रहेंगे।

श्री यादव ने बुनकरों को समस्याओं को भी उठाया और किसानों की आय दोगुनी करने के भाजपा के वायदे की याद दिलाते हुए कहा कि जिस सरकार ने एक भी मंडी न बनाई हो उसकी एमएसपी पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। श्री यादव ने पुरानी पेंशन की बहाली की भी मांग उठाई। उन्होंने किसानों के गन्ना भुगतान, नौजवानों, बुनकरों, किसानों की दूसरी समस्याओं का भी जिक्र किया और साथ ही गिरती अर्थ व्यवस्था पर चिंता जाहिर की।

फोटो स्रोत : गूगल

चुनावी मंथन से संविधान का नया अवतार

अरुण कुमार त्रिपाठी
वरिष्ठ पत्रकार

यह सही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जातिवादी, सांप्रदायिक, फासीवादी और संविधान विरोधी ताकतों को पूरी तरह से पराजित नहीं किया जा सका लेकिन उसी के साथ यह भी सही है कि उन्हें बैसाखियों पर ला दिया गया। लेकिन इस चुनाव की उससे बड़ी उपलब्धि है संविधान को फिर से प्रासंगिक किया जाना।

जिस चुनाव में शक्तिशाली नेतृत्व का व्यक्तिगत अहंकार सांप्रदायिकता के जहर के साथ फुंफकार रहा था उस चुनाव में विपक्षी दलों के गहन मंथन से उस संविधान की गरिमा फिर से हासिल कर ली गई है जिसे पिछले दस सालों से निरंतर हाशिए पर ढकेला जा रहा था। संविधान वह अमृत कलश है जिसे लेकर अब छीना झपटी मची हुई है और उसके प्रासंगिक होने और उसके मूल्यों की शरारतपूर्ण व्याख्याएं की जा रही हैं। इसलिए आवश्यकता है कि वह सही हाथों में रहे और उसकी उदार और नैतिक व्याख्या की जाए।

प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि अगर 2024 में संविधान और आरक्षण की रक्षा करने का मुद्दा था तो जनता ने यह दायित्व भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और उन्हें सौंपा है। दूसरी ओर यह असत्य भी फैलाया जा रहा है कि विपक्षी दलों ने एक झूठी कहानी गढ़ी कि अगर भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार आई तो संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। यह कहानी जनता के बीच सफलतापूर्वक पहुंच गई और जनता ने उस पर अपना मत व्यक्त करके भारतीय जनता पार्टी को कम से कम साठ सीटों का भारी नुकसान पहुंचाया।

हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने इस आशंका का बार बार खंडन किया और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब अगर बाबा साहेब आंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान को बदला या खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जनता फिल्मी संवादों और बार-बार हवा में दिए जा रहे आश्वासनों की तुलना सरकार और उसके नेताओं की करनी से कर रही थी और सरकार और उसके नेताओं की करनी कहीं भी संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं दिख रही थी न ही वह संविधान सम्मत थी। बल्कि फैजाबाद के तत्कालीन सांसद लल्लू सिंह ने तो स्पष्ट तौर पर कहा ही कि हम चार सौ पार का नारा इसलिए दे रहे हैं ताकि संविधान को बदला जा सके।

यही नहीं दक्षिण भारत के भी कुछ भाजपा सांसदों ने संविधान बदले जाने का इरादा जताया था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दिसंबर 2020 में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा था कि भारत में बहुत अधिक लोकतंत्र है। इससे आर्थिक सुधारों में परेशानी पेश आती है। चाहे वह श्रमिकों का मामला हो, खेती का मामला हो या खनन का मामला हो, हर जगह संविधान सुधार में आड़े आ जाता है। इसलिए अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो लोकतंत्र के इस राजनीतिक दायरे को समेटना होगा। मतलब संविधान को बदलना होगा।

विपक्षी दलों के गहन मंथन से उस संविधान की गरिमा फिर से हासिल कर ली गई है जिसे पिछले दस सालों से निरंतर हाशिए पर ढकेला जा रहा था। संविधान वह अमृत कलश है जिसे लेकर अब छीना झपटी मची हुई है और उसके प्रासंगिक होने और उसके मूल्यों की शरारतपूर्ण व्याख्याएं की जा रही हैं

भाजपा और उसके संघ परिवारी चिंतक लगातार यह आख्यान फैला रहे थे कि संविधान एक औपनिवेशिक दस्तावेज है। इसलिए इसके साथ भारतीयता नहीं जुड़ी है। बिना इसे बदले भारत अपने आत्म को फिर से नहीं प्राप्त कर सकता। इसी के साथ यह आख्यान भी स्थापित करने के लिए पुस्तकें लिखी गईं कि डॉ भीमराव आंबेडकर को संविधान निर्माता कहना उचित नहीं है। संविधान का प्रारूप तो बीएन राउ ने बनाया था। डॉ आंबेडकर को श्रेय देना अनुचित है। यह कहानी भी फैलाई जाती है कि संविधान तो उस संविधान सभा ने बनाया था जो जनता से सीधे चुनकर नहीं आई थी। संविधान सभा के प्रतिनिधि सीमित मताधिकार से चुनकर आए थे, इसलिए ऐसे संविधान की वैधता कहां है? वैधता हासिल करने के लिए हमें नया संविधान चाहिए।

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाई तो उन्होंने सन् 2000 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मनेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया के नेतृत्व में एक संविधान समीक्षा आयोग गठित किया। ध्यान देने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग लंबे समय से कर रही थी और अपनी(गठबंधन की) सरकार बनते ही उसने यह प्रयास शुरू कर दिया। राहत की बात यह है कि सन 2002 में वेंकटचलैया आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें संविधान के बुनियादी ढांचे में किसी तरह के बदलाव का सुझाव नहीं दिया। इस तरह भाजपा और संघ का वह प्रयास विफल हो गया।

संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किसी भी क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थान खोलने और अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस स्वतंत्रता पर तरह-तरह से हमला किया जाता रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसके निरंतर निशाने पर रहा है। मदरसों को तो आतंकवादियों का अड्डा बताकर खत्म करने का माहौल बनाया जाता रहा है।

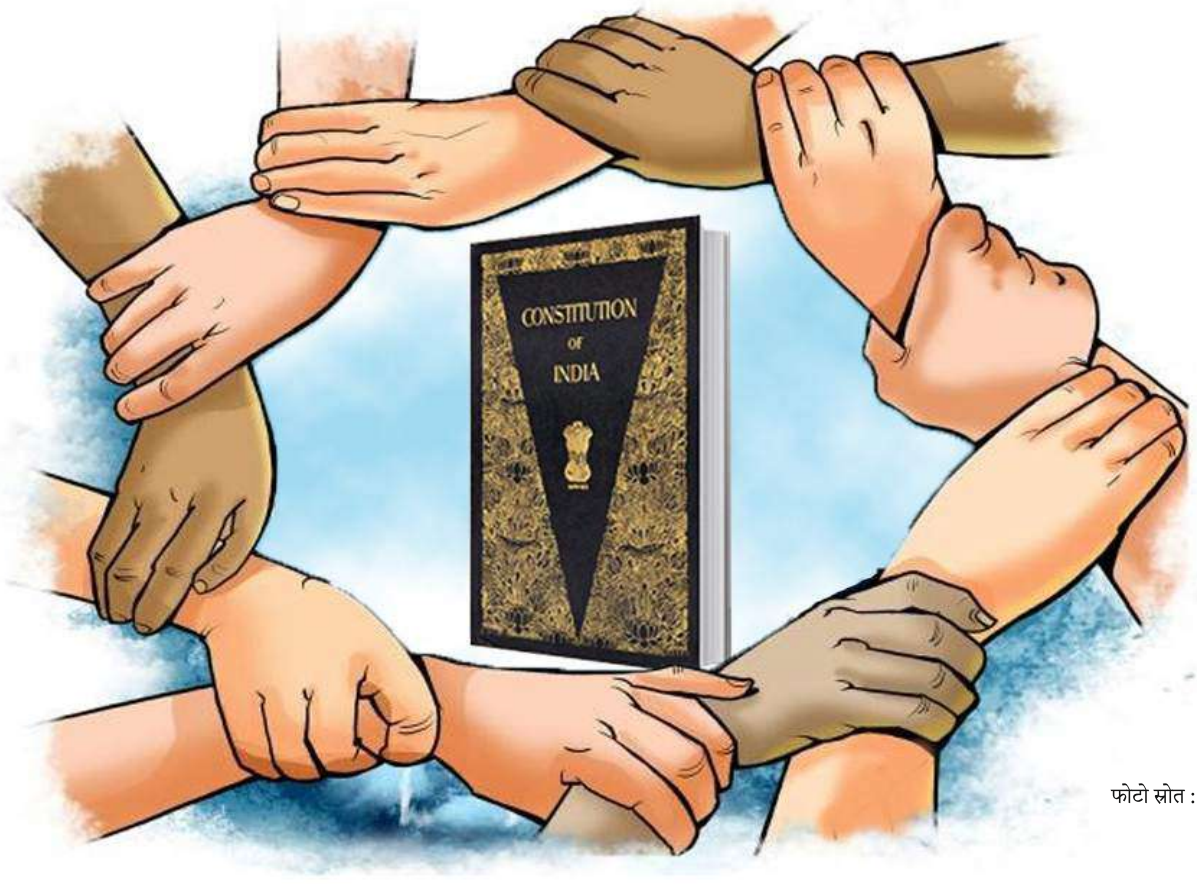

फोटो स्रोत : गूगल

संघ और भाजपा के जो लोग यह कहानी चला रहे हैं कि संविधान पर खतरे की बात एक झूठ थी और विपक्षी दलों यानी इंडिया समूह का वह झूठ चल निकला, वे वास्तव में जनता की स्मृति पर परदा डालकर एक और झूठ का प्रचार करना चाह रहे हैं। इस झूठ का प्रमाण इस बात से मिलता है कि उपराष्ट्रपति बनाए जाने के तुरंत बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने यह बहस जोरशोर से चलाई कि अब जबकि केशवानंद भारती के मुकदमे में दिए गए फैसलों की स्वर्ण जयंती आ गई है तो हमें यह तय करना चाहिए कि संविधान का बुनियादी ढांचा बताने वाले उस फैसले को कैसे समाप्त किया जाए। वे वास्तव में संविधान के बुनियादी ढांचे का कोई स्वरूप मानने को तैयार नहीं थे, ताकि अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान में मनमाफिक बदलाव किया जा सके।

इतना ही नहीं भाजपा और संघ परिवार के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पिछले दस सालों से अभियान चला रखा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। संविधान के प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाना है। इसके लिए संघ2रखी थी। सरकारी उपक्रमों का धुआंधार निजीकरण और चंद पूंजीपतियों के हाथों हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और बंदरगाह समेत तमाम सारी सार्वजनिक संपत्तियों का बेचा जाना स्पष्ट रूप से संविधान की भावना का उल्लंघन रहा है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों या राज्य की सभी धर्मों से समान दूरी के सिद्धांत का उल्लंघन किया। वे धार्मिक यात्रा और पूजन को निजी कार्यक्रम बनाने की बजाय सदैव सार्वजनिक और राज्य का कार्यक्रम बनाकर पेश करवाते हैं। उन्होंने राज्य के पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह संविधान पर हमला नहीं तो और क्या था।

मोदी और एनडीए सरकार ने पिछले दस सालों में ऐसी स्थिति ला दी है कि आप बंद हॉल में भी कोई गोष्ठी या सभा नहीं कर सकते। दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में जितनी आसानी से सभा, गोष्ठी, पुस्तकों के विमोचन हुआ करते थे वे अब प्रतिबंधित से हो गए हैं। पहले उनके लिए पुलिस से

अनुमति लीजिए और उसके बाद आखिरी समय उसके रद्द किए जाने की आशंका से जूझिए। संविधान के अनुच्छेद 19 पर इससे बड़ा हमला और क्या हो सकता है। अखबार में लिखने, चैनल पर बोलने और सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से कितने पत्रकार और नागरिक जेल की हवा खा रहे हैं या खा चुके हैं।

यूएपीए(आतंकवाद विरोधी कानून) और पीएमएलए(मनीलांडरिंग रोकने वाला कानून) ऐसे निवारक नजरबंदी प्रावधान बन चुके हैं कि उसके तहत कभी पत्रकार, लेखक और बौद्धिकों को जेल में सड़ा दिया जाता है तो कभी राजनेताओं और मुख्यमंत्रियों को आधी रात को पकड़ कर जेल में ठूंस दिया जाता है। फिर निचली अदालत से जमानत की बात तो सोचिए नहीं। अगर यूएपीए और पीएमएलए के मामले में किसी की जमानत होती है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ही।

इन स्थितियों ने भारत के संविधान के भाग तीन में वर्णित मौलिक अधिकारों को बेअसर कर दिया है। अगर अनुच्छेद 19 में दी गई अभिव्यक्ति की आजादी छीनी गई है तो अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार भी ग्रहणग्रस्त है।

चुनावी मंथन से संविधान के नए अवतार, विपक्ष की बढ़ी शक्ति, भाजपा की घटी सीटें और इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष के लिए अवमानना से भरे प्रधानमंत्री को देखकर क्या लगता है? क्या कुछ बदला है या सब कुछ वैसे ही है? यह सवाल हर ओर पूछा जा रहा है और एक तरफ कहा जा रहा है कि कुछ नहीं बदला है तो दूसरी ओर कहा जा रहा है कि सत्तापक्ष अब संभल कर चलेगा और वह विपक्ष के उसी आख्यान को अपना बना रहा है जिसने उसे सर्वाधिक आहत किया है।

इसलिए यह सवाल उठता है कि विपक्ष क्या करे? क्या वह संविधान की प्रतियां लहराता रहे और उसकी सौगंध खाता रहे और लोकतंत्र को बचाने का दावा करता रहे या इन मोटे शीर्षकों से आगे कुछ करे? स्पष्ट तौर पर संविधान की प्रतियां लहराने और बाबा साहेब का नाम लेकर उसे संरक्षित करके के आह्वान से जितनी बात होनी थी वह हो चुकी। बल्कि समाजवादी पार्टी ने जिस पीडीए की रणनीति पर चुनाव जीता अब तो भाजपा भी उसे अपनाने की कोशिश में है। चूंकि समाजवादी पार्टी की इस रणनीति ने भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को चित्त कर दिया, इसलिए अब भाजपा के कई पराजित उम्मीदवार डीपीए चलाने की कोशिश कर रहे हैं। डीपीए यानी दलित पिछड़ा और अगड़ा।

जिस तरह से कभी नूरानी के जवाब में बाजार में तूरानी आया था उसी प्रकार अब पीडीए के जवाब में डीपीए आ रहा है। मोहनलालगंज से चुनाव हारे भाजपा के कौशल किशोर ने डीपीए के नाम पर यात्रा शुरू करने की सोची है। संविधान की रक्षा की बात तो एनडीए के लोग जोरशोर से कर ही रहे हैं। वे कह भी रहे हैं कि दलितों पिछड़ों

फाइल फोटो

सत्यमेव
जयते

फाइल फोटो

का आरक्षण कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन वास्तव में दलित पिछड़े इस बात को समझ गए हैं कि भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग जो जाति जनगणना से इंकार करती है वह भला कैसे दलितों पिछड़ों को उनकी आबादी के लिहाज से हक देने वाली है।

जब सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही हैं तो आरक्षण का मकसद क्या बच रहा है? बल्कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश की सरकार को पत्र लिखकर यह बता दिया है कि सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होने वाली भर्तियों में कैसे पिछड़ों और दलितों की सीटों को एनएफएस(उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला) घोषित कर दिया जाता है। फिर उन सीटों का सामान्य सीट घोषित कर दिया जाता है। उनका यह पत्र भाजपा के पिछड़ा दलित हितैषी होने के दावे की कलई खोल देता है।

अगर इंडिया समूह को संविधान को आधार बनाकर राजनीति करनी है तो उन्हें संविधान की प्रतियां लहराने से आगे जाना होगा। उन्हें आम जनता को बताना होगा कि संविधान की इस पुस्तक के भीतर क्या लिखा है और कैसे वह देश के हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देती है। देश का नागरिक पुलिस प्रशासन के समक्ष आज भी गरिमापूर्ण जीवन नहीं प्राप्त कर सका है। दरअसल संविधान के दो मूल उद्देश्य हैं। इस बात को संविधान के इतिहासकार ग्रैनविल आस्टिन अपनी पुस्तक `कारनर स्टोन आफ ए नेशन' में लिखते हैं। उनका कहना है कि एक उद्देश्य तो देश की एकता और अखंडता कायम करने का है तो दूसरा उद्देश्य सामाजिक क्रांति का है।

इंडिया समूह को चाहिए कि वह संविधान के सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को संवैधानिक दायरे में आगे बढ़ाए। इसमें मौलिक अधिकारों के साथ ही जाति जनगणना का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है और सामाजिक न्याय के दूसरे कार्यक्रम हैं। इसी में लोकतंत्र का भी विस्तार होगा और इसी में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा। इसी के माध्यम से भाजपा के फर्जी संविधानवाद और इंडिया के असली संविधानवाद की टक्कर होगी और जनता असली वाले की पहचान कर सकेगी। तभी संविधान सही हाथों में जाएगा और उसकी रक्षा हो सकेगी। यही संविधान के इस नए अवतार का मतलब है।

अखिलेश के जन्मदिन पर PDA की मजबूती का संकल्प

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक जुलाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित किए और श्री अखिलेश यादव के उत्तम स्वास्थ्य के साथ दीर्घायु की कामना की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के जन्मदिन पर PDA को और मजबूत करने का संकल्प भी लिया।

जन्मदिन की बधाइयां देने पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री

अखिलेश यादव ने शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए कहा कि PDA सबको जोड़ता है। यह आरएसएस की लगने वाली शाखाओं का जवाब है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा की नफरती राजनीति को रोकने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर नेताजी का सपना पूरा किया है।

श्री यादव ने कहा कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत भाजपा की तानाशाही और सांप्रदायिकता की पराजय है। भाजपा ने तीन नए कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का हनन कर संविधान पर हमला किया। लोकतंत्र में यह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी-पीडीए की संविधान और लोकतंत्र बचाने की यह लड़ाई अभी जारी रहेगी।

श्री अखिलेश यादव के 51वें जन्म दिन को कार्यकर्ताओं ने स्वत: स्फूर्त ढंग से हर्ष के साथ मनाते हुए केक काटा, मिठाइयां बांटीं। राज्य मुख्यालय लखनऊ पर हजारों की तादाद में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अपने प्रिय नेता श्री अखिलेश यादव को फूल मालाओं से लाद दिया। उन्हें गुलदस्ते देकर बधाइयां दीं। बधाई देने वालों में समाज के सभी तबकों के लोग शामिल रहे।

उनके जन्मदिन के अवसर पर देश और प्रदेश में कई स्थानों पर केक काटा गया, वृक्षारोपण के साथ मिष्ठान, फल, गरीबों में अन्नदान, भंडारे आदि के आयोजन भी किए गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पतालों में मरीजों के बीच फल भी बांटे। श्री अखिलेश यादव की दीर्घायु के लिए हवन-पूजन के कार्यक्रम भी हुए। राज्य मुख्यालय पर पहुंचकर राज पुरोहित पं हरिप्रसाद ने स्वस्तिवाचन कर आशीर्वाद दिया। पूर्व सांसद उदय प्रताप सिंह ने श्री अखिलेश यादव के शतायु होने की कामना की।

समाजवादी किन्नर सभा की अध्यक्ष पायल सिंह ने श्री अखिलेश यादव की आरती उतारी और दीर्घायु होने की कामना की। चित्रकूट के विधायक अनिल प्रधान ने नेताजी की प्रतिमा भेंट की। पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन ने बरगद का पौधा और जानकी पाल ने पौधा भेंट किया। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने गीत संगीत के विभिन्न कार्यक्रम पेश किए।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर नगर निगम पार्षद दल के उपनेता देवेन्द्र सिंह जीतू तथा वरिष्ठ नेता नवीन धवन बंटी, मंजीत सिंह तथा धीरज यादव द्वारा भंडारा आयोजित किया गया। भंडारा का उद्घाटन राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने किया। श्री रोहित शुक्ल ने भी भंडारा किया। श्री महेश चौरसिया ने आम वितरित किए। वरिष्ठ नेता संतोष पांडेय ने केक काटकर और मिष्ठान वितरण कर श्री अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। कैसरबाग, लखनऊ स्थित महानगर कार्यालय में नगर अध्यक्ष फाकिर सिद्दीकी ने भंडारा का आयोजन किया।

श्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर आर्थिक रूप से कमजोर 100 बच्चों को समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती जूही सिंह ने लैपटॉप और टैबलेट भेंट किए। साथ ही श्रीमती जूही सिंह द्वारा पांच गांवों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संसाधन उपलब्ध कराने के साथ पुरस्कार भी दिया गया।

समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष सिकन्दर यादव एडवोकेट के नेतृत्व में अनाथ बच्चों के साथ श्री अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया।

जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 30 जून को गोमती नदी के किनारे हनुमान सेतु पर श्री अखिलेश यादव के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए लखनऊ उत्तरी

जिला समाजवादी

विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी सुश्री पूजा शुक्ला ने भंडारे का आयोजन किया। हजरतगंज स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर परिसर में पूर्व महानगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित ने श्री अखिलेश यादव के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना के लिए हवन पूजन का आयोजन किया। समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी. पांडे के नेतृत्व में लखनऊ के बिजनौर स्थित मलिन बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल, केक आदि का वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्री अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर केक काटे और अस्पतालों व गरीबों के बीच जाकर उनमें मिठाइयों व फलों का वितरण किया।

अखिलेश यादव यानी विकास का पर्याय

फाइल फोटो

राजेन्द्र चौधरी

समाजवादी सरकार के दौरान मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में विकसित करने की दिशा में कार्य किया था। एक्सप्रेस वे, हाईवे, रिवर फ्रंट, नदियों की सफाई, खेलों का विकास, स्टेडियम का निर्माण और खेल सुविधाओं के लिए आधारभूत ढांचा बनाने का कार्य, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निर्माण, गांवो में सुविधाओं का विकास, खेती और किसानी के लिए नई-नई योजनाएं, बिजली क्षेत्र में कार्य और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस को नए तरीके से तैयार करने का काम किया था।

जबकि भाजपा सरकार ने पिछले 7 साल में सब कुछ बर्बाद कर दिया, भाजपा ने एक भी विद्युत उत्पादन की इकाई नहीं लगाई, विकास को रोक दिया। राजनीतिक द्वेष भावना से कार्य किया।

जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (JPNIC) का कार्य रोककर और अवरोध पैदा कर लोकनायक के सम्मान को भी भाजपा सरकार ने अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं समाजवादी सरकार में श्री अखिलेश यादव ने सभी कार्य विश्व स्तरीय किए हैं।

श्री अखिलेश यादव के कार्यों की सराहना पूरे देश और दुनिया में हो रही है। श्री अखिलेश यादव द्वारा किए गए कार्य आज देश में उदाहरण के तौर पर लिए जाते हैं। विश्व स्तरीय लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, इकाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स सिटी या गोमती रिवर फ्रंट और उसके किनारे बनाया गया स्टेडियम व अन्य सुविधाएं।

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर श्री अखिलेश यादव ने देश में पहली बार लड़ाकू विमान और मालवाही जहाज को सड़क पर उतार कर अपने विकास के विजन को पूरे देश और दुनिया के सामने रखने का काम किया। देश की सबसे बड़ी सड़क आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को अखिलेश यादव ने रिकॉर्ड 22 महीने में बना दिया।

फाइल फोटो

श्री अखिलेश यादव द्वारा खेल के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए समाजवादी सरकार में शहीद पथ के किनारे स्पोर्ट्स सिटी की आधारशिला रखी गई। इस स्पोर्टस सिटी में बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय इकाना क्रिकेट स्टेडियम आज दुनिया में अपनी पहचान बन चुका है। यह श्री अखिलेश यादव की देन है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर और वर्ल्ड कप के मैच लखनऊ में हो रहे हैं।

इकाना स्पोर्टस सिटी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के साथ-साथ इंटरनेशनल स्तर का फुटबॉल स्टेडियम, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट बनकर तैयार हो गया है। टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल समेत अन्य खेल भी हो सकेंगे।

श्री अखिलेश यादव ने गोमती नदी की सफाई कराकर उस पर रिवर फ्रंट बनाकर देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ-साथ युवाओं को खेलने के लिए क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया। श्री अखिलेश यादव गोमती के किनारो को लंदन की टेम्स नदी की तरह विकसित करना चाहते थे। लेकिन भाजपा सरकार में अखिलेश यादव की सभी विकास परियोजनाएं संकीर्ण राजनीति का शिकार हो गईं।

भाजपा सरकार को समाजवादी सरकार में हुए विकास कार्यों का नाम बदल कर उसका श्रेय लेने में महारत हासिल है। भाजपा की पूरी सरकार संकीर्ण और क्षुद्र मानसिकता की शिकार है। उसने श्री अखिलेश यादव जी द्वारा बनवाए गए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला, कैंसर संस्थान का नाम बदला, मेडिकल कॉलेज के नाम बदले लेकिन कभी भी यह नहीं बताया कि यह सभी कार्य समाजवादी सरकार में श्री अखिलेश यादव जी ने कराये थे। मेट्रो जहां तक समाजवादी सरकार में चली थी, उससे आगे नहीं बढ़ी।

भाजपा सरकार में जितने भी काम हुए हैं सब भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं। लूट और झूठ भाजपा की पहचान है। भाजपा सरकार में जो भी कार्य हुए हैं उसमें जमकर कमीशनखोरी हुई है। फलतः बेहद घटिया निर्माण हुए। वह सब आम जनता के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से लेकर अयोध्या में हुए घटिया निर्माण कार्य भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं।

(लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं)

PDA वृक्षारोपण अभियान

हरियाली बढ़ाने का संदेश

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक PDA पेड़ वृक्षारोपण अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव और शहर के मोहल्लों, कस्बों में उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने P D A पेड़ वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं

हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया। व्यापक पैमाने पर चले इस अभियान में पूरे प्रदेश में विभिन्न प्रजातियां खासकर पीपल, बरगद और नीम के लाखों पेड़ PDA के नाम रोपे गए।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने 7 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय परिसर लखनऊ में स्वयं बरगद के पेड़ का रोपण कर अभियान का समापन किया।

बरगद का पेड़ रोपने के बाद श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पृथ्वी को हरा-भरा रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाना और उनकी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। आज ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गई है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वृक्षावरण और वनावरण बढ़ाना जरूरी है। समाजवादी सरकार के समय उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण के बढ़ाने की दिशा में काफी कार्य हुए थे। नदियों, झीलों, नहरों के किनारे पार्कों में खाली स्थानों पर बड़ें पैमाने पर पेड़ लगाए गए थे, साथ ही लगाए गये पेड़ों की देखभाल की गई थी।

उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में राजधानी लखनऊ में बनाए गए डॉ राम मनोहर लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, गोमती रिवरफ्रंट, पीजीआई में लगाए गए पेड़ इसके उदाहरण हैं। इसी तरह से पूरे प्रदेश में पेड़ लगाए गये। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए हर वर्ष की तरह इस साल भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर बड़ी संख्या में नीम, पीपल और बरगद के पेड़ लगाए हैं।

पर्यावरण को लेकर श्री अखिलेश यादव के प्रेम को देखते हुए पार्टी ने इस बार उनके जन्मदिन (एक जुलाई) पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का संदेश देने के लिए एक सप्ताह तक, 1 जुलाई से 7 जुलाई पूरे प्रदेश में PDA पेड़ वृक्षारोपण अभियान चलाया।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने 5 जुलाई को इटावा के श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में

PDA

माँ चन्द्रिका देवी मन्दिर
(सेवादार)

श यादव जी जन्मदिन के उपलक्ष्य में
प्ताहिक
क्षारोपण
कार्यक्रम

PDA
पेड़
PDA
पेड़
PDA
पेड़
PDA

PDA पेड़ वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

इस अवसर पर प्रो यादव ने कहा कि PDA पेड़ रोपण अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। वर्तमान में हर तरफ फैले हुए तरह-तरह के प्रदूषण को दूर करने के लिए आवश्यकता पेड़ की है, शाखाओं की नहीं।

जब पौधे की जड़ें जमीन पकड़ लेती हैं तो शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल सब अपने आप प्राप्त होता है। वे शाखाएं अप्राकृतिक होती हैं जिनकी न तो जड़ों का पता होता है, और न ही इस बात का कि उनका फल किसको मिल रहा है। इसलिए आवश्यकता जमीन से जुड़े पेड़ों की है, मनुष्य निर्मित शाखाओं की नहीं।

उन्होंने कहा कि PDA पेड़ पौधारोपण के इस पर्यावरणीय, सामाजिक आंदोलन को समाजवादी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश के गांवों से शुरू करके आगामी चरणों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का प्रयास किया जाएगा।

6 जुलाई को सांसद आदित्य यादव ने बदायूं के दातागंज विधानसभा क्षेत्र के हरे नगला ग्रामसभा में पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 7 जुलाई को बाराबंकी जनपद में भयारा गांव में सपा के वरिष्ठ नेता राकेश वर्मा, सांसद तनुज पुनिया, पूर्व सांसद पीएल पुनिया, विधायक गौरव रावत की मौजूदगी में PDA पेड़ों का रोपण मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के हाथों हुआ।

युवाओं के हक में सड़क पर उतरे सपा कार्यकर्ता

बुलेटिन ब्यूरो

नीट व दूसरी परीक्षाओं के लगातार पेपर लीक होने से परेशान छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार मुखर है। युवाओं के अधिकारों के लिए समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। युवाओं के हक की आवाज को दबाने के लिए भाजपा सरकार कार्यकताओं के दमन पर उतर आई है लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता डटे हुए हैं।

15 जून को समाजवादी छात्र सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के गेट पर मेडिकल छात्रों के साथ धरना दिया। धरने में नीट की परीक्षा रद्द कर दुबारा कराने की मांग की गई। सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ इमरान ने बताया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण व छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

25 जून को समाजवादी छात्रसभा के प्रदेश अध्यक्ष इं विनीत कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन न करने के लिए रोका जिसपर कार्यकर्ता अड़

भाजपा सरकार ने भर्तियों में घोटाला किया है

बुलेटिन ब्यूरो

मेडिकल प्रवेश परीक्षा से लेकर नौकरियों की तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक होने से अधर में लटके छात्रों-नौजवानों के भविष्य को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव काफी चिंतित हैं। वह लगातार इस मसले पर आवाज उठा रहे हैं।

10 जुलाई को श्री यादव ने सैफई में छात्रों-नौजवानों की बैठक में उनकी समस्याएं सुनीं और उनकी चिंता में खुद को शामिल किया।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने नौकरियों की भर्तियों में घोटाला किया है। हाईकोर्ट में खुलासा हुआ है कि कापियां तक बदल दी गईं। ये अपने लोगों को नौकरियों में एडजस्ट करने के लिए घोटाला करते हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि सैफई मेडिकल कालेज में एक ही कोचिंग के बच्चों को बड़े पैमाने पर नौकरी कैसे मिल गईं? सैफई के साथ लखनऊ के अन्य मेडिकल संस्थानों में भी यही हुआ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना, भाजपा सरकार की सत्यनिष्ठा पर सवालिया निशान है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार नौकरियों में आरक्षण नहीं देना चाहती है इसलिए भर्तियों में घपले और घोटाले करती है। ये पिछड़े, दलितों और पीडीए परिवार को साजिश के तहत नौकरियों से दूर रखने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा सरकार ने नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर नकल माफिया के हवाले कर दिया है। यह सरकार एक भी परीक्षा पारदर्शिता से कराने की क्षमता नहीं रखती है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में सराबोर है।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 साल की सरकार में पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया है। यह सरकार छात्रों, युवाओं के साथ-साथ देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। छात्रों की मेहनत पर पानी फेर रही है। उन्होंने कहा कि ये आरोप बेहद गंभीर हैं कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित करवाने वाली गुजरात की कंपनी ने ही पेपर लीक करवाया। यह और गंभीर है कि जब कंपनी का मालिक विदेश भाग गया, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बारे में जनता को बताया। जनता के गुस्से से बचने और दिखाने भर के लिए उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया।

बीजेपी सरकर वीक है
सारे पेपर लीक है।
समाजवादी छात्र सभा अंबिका

गए। पुलिस से नोंकझोंक में एक कार्यकर्ता का हाथ टूट गया। बाद में युवाओं के हक की आवाज बुलंद कर रहे इन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

21 जून को समाजवादी छात्र सभा ने नीट परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के विरोध में राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में नीट परीक्षा रद्द कर दुबारा कराने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे समाजवादी छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

10 जुलाई को नीट परीक्षा में हुई धांधली और लगातार पेपर लीक से परेशान छात्र, युवाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर INDIA गठबंधन के युवा दलों के नेतृत्व में विशाल सभा कर विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने भी इसमें बढ़चढकर हिस्सा लिया। सभा में समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फहद ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार हो रहे पर्चा लीक से छात्र, नौजवान हताश और निराश है।

बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंसती युवा पीढ़ी

डॉ लक्ष्मण यादव

दुनिया का सबसे युवा देश है भारत। हमारे देश की दो-तिहाई आबादी युवाओं की है। यह किसी भी विकासशील देश के लिए असीमित संभावनाओं की गुंजाइश है। मगर इन युवाओं के साथ क्या न्याय हो पा रहा है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (ILO) ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट (IHD) के साथ मिलकर 'इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024' जारी की। इसके मुताबिक़ अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं, तो उसमें से 83 लोग युवा हैं। इसमें भी ज्यादातर युवा शिक्षित हैं।

यह किसी भी समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे वक्त में देश की राजनीति के बुनियादी मुद्दे क्या हैं? क्या पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, मंहगाई हमारे दौर की राजनीति के मूल मुद्दे हैं? नहीं। हमारे दौर की राजनीति के बुनियादी मुद्दे सामाजिक-

आर्थिक नहीं, धार्मिक हैं। 'मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा से होते हुए भैंस खोल ले जाएंगे' जैसे जुमले बोलकर हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव लड़े गये। ग़नीमत है कि विपक्ष में चुनावी मुद्दों में भी पेपर लीक और बेरोज़गारी जैसे मसले गंभीरता से शामिल रहे। आम-आवाम ने इसे समझा और अहमियत भी दी। अन्यथा सत्ताधारी ख़ेमा युवाओं के इन सरोकारों को पकौड़ों से लेकर दंगाई सियासत के बीच महदूद कर देने में कामयाब हो जाता।

पेपर लीक व बेरोजगारी के पीछे की सियासत

पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, मंहगाई पर न तो कथित मुख्यधारा मीडिया बहस करता है और न सत्ताधारी ख़ेमा बहस होने देना चाहता है। शिक्षा और रोज़गार पर गंभीरता से बात तब होती है, जब या तो युवा हारकर आत्महत्या कर ले या पेपर-लीक जैसी साज़िशों की ख़बरें दुर्घटनावश सामने आ जाएं। ऐसा होना युवाओं या उनके परिवारों की निजी क्षति मात्र नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की परियोजना को बाधित करता है। युवा बेरोज़गार हैं, तो ये निजी नहीं, राष्ट्र की चिंता होनी चाहिए। चंद ताकतवर पूंजीपतियों को सस्ता श्रम चाहिए और नकारात्मक विभाजनकारी राजनीति को अविवेकी भीड़। इन दोनों के गठजोड़ ने भारत में बेरोज़गारी के 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

साप्ताहिक इंडिया टुडे के जून 2024 के अंक में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सात साल में सत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। अकेले उत्तर प्रदेश में ही साल 2017 से लेकर साल 2023 के बीच तक़रीबन डेढ़ दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश में दो-दो बार यूपी बोर्ड की परीक्षा के पेपर भी लीक हो चुके हैं। यह पेपर लीक के सांस्थानिक, सुनियोजित व संरक्षण प्राप्त साज़िश की तरफ़ इशारा करता है। NEET के आरोपियों ने मीडिया में बयान दिया कि 30 से 32 लाख रुपये में सौदा होता रहा।

आज भी देश के विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों और सरकारी नौकरियों में में 90 फ़ीसदी आबादी वाले PDA यानी पिछड़े दलित आदिवासी-अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी दस फ़ीसदी भी नहीं है। ऐसे में अनियंत्रित बेरोज़गारी और पेपर लीक जैसी साजिशों से सबसे ज़्यादा और पहला नुक़सान उनका होता है, जिन्हें सबसे बाद में हिस्सेदारी मिलनी शुरू हुई थी

सामाजिक न्याय और आरक्षण से रिश्ता

मंडल आंदोलन ने आज़ाद भारत में सामाजिक परिवर्तन की विभाजन रेखा खींची है। नब्बे के बाद पहली बार व्यवस्थित तौर पर देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक व महिलाएं शिक्षा व रोज़गार में आने शुरू हुए। उसके पहले नॉट-अवेलेबल कहकर उनकी जगहों पर किसी और को रोज़गार मिलता रहा। जब ये अवेलेबल हुए, तो NFS यानी 'नॉट फ़ाउंड सुटेबल' कहकर इन्हें रोका गया। ये साज़िशें आज भी बदस्तूर जारी हैं।

ऐसी साज़िशों के चलते आज भी देश के विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों और सरकारी नौकरियों में में 90 फ़ीसदी आबादी वाले PDA यानी पिछड़े दलित आदिवासी-अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी दस फ़ीसदी भी नहीं है। ऐसे में अनियंत्रित बेरोज़गारी और पेपर लीक जैसी साज़िशों से सबसे ज़्यादा और पहला नुक़सान उनका होता है, जिन्हें सबसे बाद में हिस्सेदारी मिलनी शुरू हुई थी। आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा वक्त में देश का नब्बे फ़ीसदी से ज़्यादा रोज़गार असंगठित क्षेत्र में है। दस फ़ीसदी से भी कम संगठित क्षेत्र में नौकरियां हैं। उनमें भी कमोबेश एक फ़ीसदी नौकरियां ही सरकारी हैं। इन एक फ़ीसदी नौकरियों में ही आरक्षण लागू होता है। सत्ता में बैठे दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग आरक्षण की सामाजिक न्याय परक अवधारणा के ख़िलाफ़ हैं। नतीजतन आरक्षण न देना पड़े, इसका अन्योन्याश्रित संबंध निजीकरण, पेपर लीक और बेरोज़गारी से सीधे जुड़ता है।

निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं। असंगठित क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं। मगर जहां आरक्षण है, उन्हें लगातार निजी हाथों में बेचा जा रहा। जो बचा है, वहां पेपर लीक और भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर स्थाई नौकरी देनी पड़ेगी, तो बाबा साहब के संविधान और मंडल कमीशन के चलते आधे मौक़ों पर PDA को मौक़ा मिलेगा। मौजूदा सत्ता ये हक़ नहीं देना चाहती है, इसलिए भी ऐसी साज़िशें करती जा रही है।

समाजवादी संघर्ष की विरासत और युवा

एक ज़माने में समाजवादी आंदोलन के नारे

सड़कों पर गुलज़ार हुआ करते थे कि- **'रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ़्ती हो', 'सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम'** । मगर आज शिक्षा और रोज़गार के सवाल निजी बना दिए गए हैं। अस्सी का दशक था। साल 1974 में गुजरात में कॉलेज व विश्वविद्यालय में मेस के खाने का दाम बढ़ गया। 'नवनिर्माण अथवा पुनर्निर्माण आंदोलन' नाम से देशव्यापी छात्र-युवा आंदोलन खड़ा हो गया। जेपी आंदोलन से मशहूर इस ऐतिहासिक दौर को उस वक्त के नौजवानों ने खड़ा किया था। जेल गए, लाठिया खाईं; मगर **'सच कहना अगर बगावत है, तो समझो हम भी बाग़ी हैं'** जैसे नारों के साथ उस वक्त की तानाशाही सत्ता को नौजवानों के इस आंदोलन ने शिकस्त दे दी। उसके बाद कई ऐसे ऐतिहासिक मोड़ आए, जब युवाओं के संगठित प्रतिरोध ने देश को अंधकार में जाने से बचाया और रचनात्मक दिशा दिखाई।

आज देश एक बड़े युवा आंदोलन की ज़रूरत महसूस कर रहा है, मगर मौजूदा दौर में संगठित छात्र-युवा आंदोलन नहीं खड़ा हो पा रहा। इसके पीछे कुछ ठोस बुनियादी वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह है सांप्रदायिक राजनीति। जब देश में युवाओं के बुनियादी मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, उस समय उन्हें ऐसी भीड़ में तब्दील किया जा रहा है, जो विभाजनकारी दक्षिणपंथी राजनीति में इस्तेमाल की जा सके। इस देश में युवाओं को क्रिकेट से लेकर सांप्रदायिक राजनीति में व्यस्त कर दिया गया है। इसलिए नौजवान या तो अशिक्षित, अविवेकी हो चुका है, या रोज़गार के सवाल को अपनी क़ाबिलियत से जोड़ खुद को ही दोषी मान बैठता है।

छात्र संघ पर प्रतिबंध का दुष्प्रभाव

छात्रसंघ लोकतंत्र की राजनैतिक नर्सरी है। भगतसिंह अपने लेख **'विद्यार्थी और राजनीति'** में विद्यार्थियों को राजनीति के लिए सजग, जागरूक, संगठित और सक्रिय रहने की बात कहते हैं। बाबा साहब डॉ. आंबेडकर का सबसे लोकप्रिय नारा ही है- **शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो।** डॉ. राममनोहर लोहिया कहा करते थे कि **अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं, तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होते हैं।** नेताजी मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि **'छात्र संघ लोकतंत्र की सातवीं इकाई है। अगर छात्र संघों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो गुंडों को, माफ़ियाओं को, धन्ना सेठों को राजनीति में आने से कोई नहीं रोक सकता है।'** एक अट्ठारह साल का नौजवान वोट देकर सरकार तो चुन लेता है, मगर अपने भविष्य को लेकर उतना सजग नहीं। छात्रसंघ हर दौर में राजनीतिक प्रशिक्षण देकर जागरूक नागरिक बोध से युक्त पीढ़ियां गढ़ता है। एक देश अपने युवाओं को

फोटो स्रोत : गूगल

फाइल फोटो

राजनीतिक ट्रेनिंग देकर भविष्य के लिए गढ़ता है, मगर भारत में दक्षिणपंथी राजनीति नौजवानों की एक अराजनीतिक पीढ़ी तैयार कर रही है।

भोजपुरी की पुरानी कहावत है **'खेलब न खेलय देब, खेलवै बिगारब'।** कल तक वर्चस्वशाली मुट्ठी भर लोग सत्ता का खेल खेलते रहे। भारत के संविधान, मंडल आंदोलन, समाजवादी आंबेडकरवादी विचारधाराओं ने जब नई पीढ़ियां तैयार करके राजनीति बदल दी, तो अब खेल बंद? छात्र-संघ को या तो अपने मुताबिक़ कर लेना या बंद कर देना इसी मानसिकता का परिचायक है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में छात्र-संघ चुनावों को भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है।

छात्र संघ में राजनीतिक रूप से तैयार पीढ़ी सवाल करती है। नौजवानों के सवालों पर संगठित प्रतिरोध करके तख़्त बदल देने की क्षमता रखती है। निजी हमलों से बचाती है। संगठित प्रतिरोध की संभावनाओं को कमजोर करके आंदोलन करने वाले नौजवानों पर झूठे मुक़दमे व जेल भेज कर दमनकारी सत्ता युवा प्रतिरोध को कुचलती जा रही है। पिछले दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फ़ीस वृद्धि आंदोलन से लेकर SSC स्कैम और अब NEET आंदोलन इसके उदाहरण हैं। यूपी में आम चुनाव के ठीक पहले पुलिस भर्ती में परीक्षा हो जाने के बाद पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हो गई। उसके बाद कई नौजवानों की आत्महत्या व अवसाद की खबरें आईं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे अपना चुनावी मुद्दा भी बनाया।

विभाजनकारी दक्षिणपंथी राजनीति की प्राथमिकता में शिक्षा व रोज़गार नहीं है। जिसके चलते युवाओं के बुनियादी मुद्दे देश की चिंता से नदारद हैं। ऐसे में यह व्यवस्थागत सवाल एक संगठित प्रतिरोध के साथ पूछे जाने की ज़रूरत है कि चुनी हुई सरकार क्यों इतनी 'वीक' है कि उसके राज में 'पेपर लीक' है। यह एक संस्थागत भ्रष्टाचार और व्यवस्थागत साज़िश की तरफ़ गम्भीर इशारा करता है। समाजवादी, संविधानवादी सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संगठनों को एक व्यवस्थित चिंतनशाला की तरह इस चिंता को लेना होगा। यह राष्ट्र निर्माण की बुनियादी ज़िम्मेदारी है।

सरकारी दावों पर भारी विस्फोटक बेरोज़गारी

प्रेम कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

आम चुनाव के नतीजे बताते हैं कि युवाओं ने मोदी 3.0 को हैसियत में ला दिया। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में युवाओं के बदले तेवर ने योगी-मोदी की नींद उड़ा दी है। 80 लोकसभा सीटों में अधिकांश पर जीत का दावा कर रही बीजेपी को महज 33 और पूरे एनडीए गठबंधन को 36 सीटें ही मिल सकीं। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत लाने से रोकने का काम निश्चित रूप से यूपी ने कर दिखाया और, इसके पीछे मेहनत रही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की। उनके पीडीए विजन ने यूपी में चमत्कार कर दिखाया।

चाहे 2022 में संपन्न यूपी का विधानसभा चुनाव हो या 2024 में लोकसभा का चुनाव- एक बात साफ हो गई कि उत्तर प्रदेश के युवा योगी-मोदी से खुश नहीं हैं और वे अखिलेश यादव की ओर हसरत भरी नज़र से देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 10 प्रतिशत से ज्यादा वोटों का फायदा और बीजेपी को सवा प्रतिशत वोटों का नुकसान इस बात की तस्दीक करती है। सीटों के टर्म में भी इसे समझा जा सकता है कि 47 सीटों वाली सपा विधानसभा चुनाव में 111 सीटों पर पहुंच गई जबकि 312 सीटों वाली बीजेपी 255 सीटों पर आ सिमटी।

घटती गई विश्वसनीयता

बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी की लोकप्रियता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विश्वसनीयता क्यों कम होती चली गयी है? और, क्यों ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है? सीएसडीएस के चुनाव बाद सर्वेक्षण बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी को पीएम मानने से ज्यादा लोग राहुल गांधी को इस पद के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं। यूपी की सियासत में यह बड़ा बदलाव है। प्रदेश स्तर पर अखिलेश यादव और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी पर स्थानीय लोग भरोसा कर रहे हैं।

पीडीए ने बदल डाली फिजां

पीडीए यानी पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक की युति ने यूपी की चुनावी फिजां को बदल डाला है। हाथ में संविधान रखने की गरज ने यह सियासत बदली है। संविधान को बचाए और बनाए रखने के लिए यह वर्ग खुलकर सामने आ चुका है। अब राम मंदिर के नाम पर बरगलाए जाते रहने को जनता तैयार नहीं है। आम लोगों को यह बात मंजूर नहीं है कि अखिलेश यादव पूजा अर्चना करें तो बाद में मूर्ति, मंदिर या मूर्ति परिसर की गंगा जल से साफ-सफाई हो। हिन्दुत्व में ऐसी भावना नही हैं लेकिन इसे ही हिन्दुत्व बताया जा रहा है। अयोध्या सीट पर बीजेपी की हार और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत नकली हिन्दुत्व पर हमले करती दिख रही है। संसद में जिस तरह से अखिलेश यादव हमलावर हुए उससे बीजेपी सहम गई। राहुल गांधी ने जिस अंदाज में बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक हमला करते हुए उन्हें 'हिंसा करने वाला' करार दिया वह अनोखी और उल्लेखनीय घटना है। जय श्री राम और हिन्दुत्व के गिर्द जो बीजेपी अपने लिए छांव ढूंढ़ा करती थी वही अब उन्हें राजनीतिक धूप की तपिश का अहसास करा रहे हैं। कर्नाटक में हारे तो नरेंद्र मोदी की टीम ने हनुमान का नाम लेना बंद कर दिया। अयोध्या हारे तो 'जय श्री राम' का नारा, लोकसभा चुनाव के बाद विजय उत्सव तक में नहीं लगाया गया। स्वयं नरेंद्र मोदी ने भी एक बार भी 'जय श्री राम' नहीं कहा।

युवाओं ने बीजेपी का साथ छोड़ा

सीएसडीएस का सर्वे बताता है कि इंडिया गठबंधन के गैर कांग्रेसी घटक दलों ने 12 फीसदी युवाओं को अतिरिक्त रूप से अपने साथ जोड़ा। ये युवा कौन थे जो इंडिया के साथ आ खड़े हुए? ये युवा अग्निवीर थे, पेपरलीक के भुक्तभोगी थे, रोजगार की आस में उम्मीद खो चुके लोग थे और इन लोगों में वे युवा भी शामिल थे जिन्हें रोजगार से हाथ धोना पड़ा और अचानक जो खुद को गरीबी रेखा से नीचे महसूस करने लगे थे।

बढ़ता जा रहा गुस्सा

युवाओं में मौजूद गुस्सा भी अब बीजेपी की सरकार और खासतौर से मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत होता चला जा रहा है। NEET की परीक्षा में 24 लाख परीक्षार्थियों का भविष्य अंधकारमय है। लेकिन, मोदी सरकार इस पर चर्चा करने को भी तैयार नहीं हैं। संसद में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश जब विपक्ष ने की तो उन्हें आसन की ओर से उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गयी।

सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि पेपर लीक हुए हैं तो परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख निकल जाने के बावजूद जिस तरह से तीन अतिरिक्त मौके रजिस्ट्रेशन कराने को मिले, वह संदिग्ध है। इस राह से 35 हजार के करीब परीक्षार्थी सामने आए। जो पेपर लीक घोटाले से खुलासा हुआ है उसके मुताबिक प्रश्नपत्र के बदले हर परीक्षार्थी से 30-30 लाख रुपये लिए जा रहे थे। 30 हजार को 30 लाख से गुणा कर औसत रकम का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह 9 लाख करोड़ रुपये होता है। क्या चुनाव में फंड जुटाने के लिए तो इन पैसों का इस्तेमाल नहीं हुआ?

मेडिकल में प्रवेश की चाहत रखने वाले किशोरावस्था के ये युवा वास्तव में निर्दोष हैं। वे थकाऊ इको सिस्टम के कारण बेहद निराश हैं। उनकी आवाज़ उठाने का काम इंडिया समूह ने किया है। इसी तरह हाथरस की घटना हो या फिर एक के बाद एक गिरते पुलों की दास्तां- कहीं सरकार नज़र ही नहीं आती।

भगदड़ के पीछे...

हाथरस में भगदड़ जैसी घटनाएं देखने में तो धार्मिक प्रवृत्ति की लगती हैं लेकिन वास्तव में यह विश्वास का अंधविश्वास में बदलते जाने की घटना है। इसमें अशिक्षा और बेरोजगारी की भूमिका बड़ी है। दलित वर्ग को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने में वर्तमान राजनीति की विफलता हाथरस के लिए मूल रूप से जिम्मेदार है। सत्ता के साथ इनका गठजोड़ इस पाखंडी व्यवस्था को मजबूत करने का विकसित हो चुका तरीका भर है।

यूपी में बड़े स्तर पर बेरोजगारी है। रोजगार के रिक्त पद हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। परीक्षार्थियों को अदालतों के चक्कर लगाने को मजबूर किया जा रहा है। वे पढ़ें या अदालतों के चक्कर काटें? छोटे-मझोले उद्योगों के बंद होने से हालात और बदतर हुए हैं। बेरोजगारों में बढ़ता गुस्सा सरकार को चैन की नींद सोने नहीं देगा।

सपा के प्रति और बढ़ रहा आकर्षण

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की स्पष्ट नीति, कार्यकर्ताओं का सम्मान और सकारात्मक राजनीति के कारण उनके प्रति लोगों में विश्वास बढ़ता जाता रहा है। यही वजह है कि अन्य दलों के नेता व कार्यकर्ता तेजी के साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ताकत लगातार बढ़ रही है। दल के प्रति बढ़ते आकर्षण से उत्साहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।

4 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ में सहारनपुर के पूर्व बसपा सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व एवं समाजवादी पार्टी की नीतियों के प्रति आस्था जताते हुए सपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने इस अवसर पर समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव को मजबूती देने के लिए हर प्रयास करने का भरोसा जताया।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए सभी साथियों का आभार जताते हुए उम्मीद जताई कि वे सभी मिलकर समाजवादी पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे।

हाजी फजलुर्रहमान के साथ बड़ी संख्या में बसपा के तमाम चेयरमैन नगर पंचायत, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व मेयर प्रत्याशी, पूर्व ब्लाक प्रमुख, सदस्य जिला पंचायत, पार्षद नगर निगम, व्यापारी नेता, प्रधान, पूर्व सभासद आदि प्रमुख थे।

इसी तरह श्री अखिलेश यादव के किसानों के प्रति लगाव और स्पष्ट नजरिये से किसानों का विश्वास भी और बढ़ा है। यही वजह है कि किसान लगातार उनसे संपर्क कर अपनी समस्याएं बता रहे हैं।

उसी कड़ी में श्री अखिलेश यादव से 5 जुलाई को राज्य मुख्यालय लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और उन्हें बताया कि भविष्य में किसानों को आपसे बहुत आशाएं हैं। किसान नेताओं ने याद किया कि समाजवादी सरकार में श्री अखिलेश यादव ने किसानों के हित में कई योजनाएं लागू की थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में ग्रामीण विकास और गांव -खेती

की उन्नति के लिए बजट का 75 प्रतिशत धनराशि का प्रावधान किया गया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद देश के किसानों की आवाज उठाएंगे। किसानों ने कहा कि देश का किसान अब उनकी ओर ही देख रहा है।

किसान प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी डॉ राममनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांत और विचारों तथा नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के संघर्ष और उनके बताए रास्ते पर चलती आ रही है। डॉ राममनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जी की प्राथमिकता में ग्रामीण विकास के साथ किसान और गांव की खेती रही है। समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता में हमेशा किसान ही रहे हैं। जब तक किसानों की सरकार नहीं बनेगी तक तब किसानों का भला नहीं हो सकता है।

सपा के प्रति भरोसा बढ़ने की एक और बानगी तब दिखी जब बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, साहित्यकारों और प्रबुद्ध नागरिकों की एक बैठक सांझी दुनिया कार्यालय लखनऊ में हुई और सिविल सोसाइटी की ओर से हस्ताक्षरित एक पत्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के लिए पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी को सौंपा गया।

26 जून को हुई बैठक की अध्यक्षता लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो रूपरेखा वर्मा ने की जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक में प्रो रूपरेखा वर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान की रक्षा और गरीब जनता के हित में जो संघर्ष समाजवादी पार्टी और इंडिया

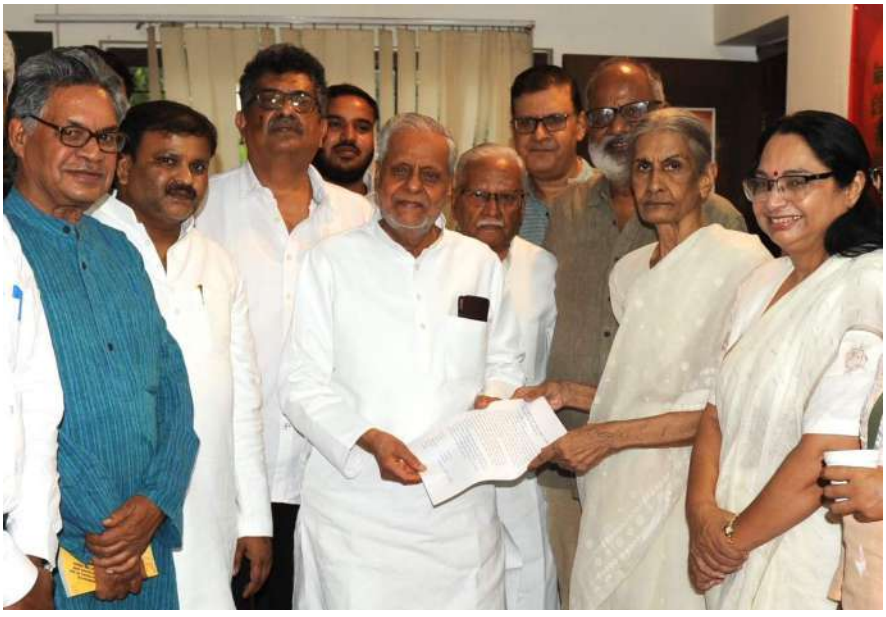

गठबंधन ने किया उससे नफरत के सौदागरों को शिकस्त मिली। नागरिक समाज ने श्री अखिलेश यादव का अभिनंदन करते हुए उनकी और गठबंधन के सभी घटकों की प्रशंसा की। बैठक में लोकतंत्र और संविधान पर हमले की आशंका को देखते हुए श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में संसद से सड़क तक संघर्ष जारी रखने में नागरिक समाज के सहयोग का भी भरोसा दिलाया गया।

सिविल सोसाइटी की ओर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को संबोधित पत्र में कहा गया है कि "2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक के रूप में और उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आपने जिस तरह साधारण जनता के मुद्दों की पैरवी की और जिस तरह भारतीय संविधान की रक्षा के लिए जोरदार लड़ाई लड़ी उसके लिए आपको हमारा साधुवाद।

पत्र में कहा गया है कि आपके और जनता के संकल्पित प्रयास से संविधान विरोधियों को मात देने का यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए अन्यथा वह फिर लामबंद होंगे और नफरत का खेल खेलेंगे। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का खतरा अभी टला नहीं है इसलिए लगातार सजग रहने की जरूरत है। संसद से सड़क तक का सजग संघर्ष आपके और नागरिक समाज दोनों के माध्यम से जारी रहेगा, ये हमारी आशा है और आपसे अपेक्षा भी।

पत्र पर प्रो रूपरेखा वर्माके अलावा इप्टा नाट्य निर्देशक राकेश वेदा, साहित्यकार वीरेन्द्र यादव, राजनीति शास्त्र पूर्व विभागाध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय प्रो रमेश दीक्षित, पूर्व प्रत्याशी मेयर वंदना मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय लाल बहादुर सिंह, व्यंग्य लेखक राजीव ध्यानी, एपवा कार्यकर्ता मीना सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता एवं टिप्पणीकार अतहर हुसैन आदि के हस्ताक्षर हैं।

भामाशाह
त्याग-सत्यनिष्ठा की मिसाल

बुलेटिन ब्यूरो

महान राष्ट्रभक्त व व्यापारियों के मसीहा भामाशाह की जयंती पर 29 जून को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया।

समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में श्री अखिलेश यादव ने भामाशाह के कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भामाशाह का पूरा जीवन त्याग और सत्यनिष्ठा का उदाहरण है। मातृभूमि के प्रति उनमें अगाध प्रेम था। उन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को अपनी संपूर्ण धन संपदा अर्पित कर दी थी। इस धनराशि से महाराणा प्रताप ने नया सैन्य बल गठित कर मेवाड़ की रक्षा की। भामाशाह के जीवन से निष्ठा, समर्पण और त्याग की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।

जयंती कार्यक्रम में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वैश्य व व्यापारी समाज का उत्पीड़न हो रहा है। आज वैश्य व व्यापारी समाज भाजपा शासन में सबसे ज़्यादा पीड़ित है। जीएसटी से बड़े पैमाने पर व्यापार का नुकसान हुआ है। व्यापारी व वैश्य समाज भी अब ये मानता है कि व्यापारी और वैश्य समाज का सम्मान केवल सपा सरकार में ही संभव है।

श्री अखिलेश यादव ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि सपा सरकार बनने पर व्यापारी व वैश्य समाज को उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा। इस अवसर पर सर्वश्री शिवपाल सिंह यादव, बलराम यादव, राजेन्द्र चौधरी, श्याम लाल पाल आदि ने भी भामाशाह के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

वीरांगना ऊदादेवी को श्रद्धांजलि

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी ने 30 जून को वीरांगना ऊदादेवी की 151वीं जयंती सादगी से मनाई। प्रदेश के सभी जिलों पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी के चित्र पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी और सिकंदरबाग स्थित स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना ऊदा देवी के चित्र पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने माल्यार्पण कर नमन किया।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने वीरांगना ऊदा देवी की वीरता को रेखांकित करते हुए बताया कि 1857 की क्रांति में ऊदादेवी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लखनऊ के सिकंदरबाग में अंग्रेज फौज के पहुंचने से पहले ऊदादेवी ने पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। अंग्रेज फौज ने वीरांगना को मार गिराया। उनकी वीरता और बलिदान इतिहास का एक अमर पृष्ठ है।

समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में वीरांगना ऊदादेवी को सर्वश्री सी.एल. वर्मा, मनोज कुमार पाल, तारिक खान, आशुतोष यादव, दिनेश सिंह, एस.के. राय, डॉ हरिश्चन्द्र तथा सिकंदरबाग चौराहे पर स्थित वीरांगना ऊदादेवी की प्रतिमा पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के अलावा प्रदेश महासचिव अताउर्रहमान, पूर्व विधायक अम्बरीष पुष्कर आदि ने श्रद्धासुमन भेंट कर उनके शौर्य एवं देशभक्ति की सराहना की।

साहस-स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति महारानी दुर्गावती

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर 24 जून को पूरे उत्तर प्रदेश में वीरांगना महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रमों में महारानी दुर्गावती के साहस, स्वामिभान को याद करते हुए उन्हें साहस, स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति बताया गया जो स्वतंत्रता के लिए कुर्बान हो गईं।

बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में वक्ताओं ने बताया कि गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती गढ़ मण्डला की रानी थीं। वर्तमान में जबलपुर उनके राज्य का केन्द्र था। 24 जून 1565 ई को महारानी ने राज्य की संप्रभुता बचाए रखने, स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी।

राज्य मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, पूर्व सांसद अरविंद कुमार सिंह, डॉ राजपाल कश्यप ने माल्यार्पण कर महारानी दुर्गावती को नमन किया।

साफ़ और बेबाक

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

Socialist Leader of India. Chief Minister of UP (2012 - 2017)

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

लेकर देश की जनता का पैगाम
हम दिल्ली आए बचाने संविधान

Translate post

Akhilesh Yadav @yadavakhile... · 03 Jul

15 अगस्त 1947 अगर 'औपनिवेशिक राजनीति' से आज़ादी का दिन था, तो 4 जून 2024 देश के लिए 'साम्प्रदायिक राजनीति' से आज़ादी का दिन रहा।
- ये साम्प्रदायिक राजनीति के अंत और सामुदायिक राजनीति की शुरुआत है।
- ये नव आशावाद, नयी उम्मीद के युग की शुरुआत है।
- इसने तोड़नेवाली राजनीति को तोड़ Show more

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

ये है झूठे विकास के गुजरात मॉडल का सच ... दस-बीस हज़ार रूपये के लिए आई कुछ रिक्तियों के लिए हज़ारों का जमावड़ा। भाजपा ने देश भर के युवाओं को अपनी नीतियों की वजह से बेरोज़गारी के महासागर में धकेल दिया है। यही वो युवा हैं जो भाजपा सरकार को हटाकर अपने भविष्य का रास्ता बनाएंगे क्योंकि जब तक भाजपा है तब तक कोई उम्मीद नहीं।

Translate post

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

आज नई शपथ संग नया पथ
PDA मंज़िल, PDA ही सफ़र

Translate post

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

भाजपा राज में 'तहसील और थाने के अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार' पर भाजपा के लोग ही जब प्रमाणपत्र बाँट रहे हैं तो क्या इस अकल्पनीय 'भाजपाई भ्रष्टाचार' पर कार्रवाई करने के लिए और कुछ सबूत चाहिए?

अब देखते हैं बुलडोज़र किस ओर मुड़ता है।

Translate post

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

नौकरी छूटने और फिर न लग पाने के दबाव में पति की आत्महत्या की सूचना मिलने पर पत्नी द्वारा भी आत्महत्या करने का दुःखद समाचार मिला।

भाजपा सरकार की नाकामी का इससे बड़ा कोई और हलफ़नामा चाहिए क्या। भाजपा को सिर्फ़ सत्ता की राजनीति से मतलब है, जनता के दुख-दर्द, बेरोज़गारी या महंगाई से नहीं।

भाजपा राज में हताश जनता से विनम्र आग्रह है कि ऐसा कोई भी क़दम न उठाएं क्योंकि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, समाधान है भाजपा सरकार का बदलना।

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

@ संसद

Translate post

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

सपा सरकार में बनी 'लखनऊ मेट्रो' के तो दूसरे चरण की शुरुआत और वाराणसी, गोरखपुर, झांसी पर कोई नहीं बात... जनता पूछ रही है ऐसे कैसे चलेगा जनाब?

Translate post

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

'हाथरस-हादसे' की दुखद सूचना मिली। सभी मृतकों को श्रद्धांजलि!

इस तरह के आयोजन में हुई मानवीय भूलों का आंकलन करने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए सबक़ लेने की भी।

एक गहन जाँच और उसके आधार पर की गयी कार्रवाई भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति को रोक सकती है।

शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं!

Following

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

INDIA की जीत की देश को बधाई!

Translate post

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

यहाँ पर इतिहास इसी तरह हर बार दोहराता है
प्रधान संसदीय क्षेत्र में क्योटो डुबकी लगाता है

#काशी
#Varanasi
#बनारस

Translate post

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

ये जो हर तरफ़ 'भ्रष्टाचार का सैलाब' है
उसके लिए भाजपा सरकार ज़िम्मेदार है

#Ayodhya

Translate post

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

विवाह की बधाई और सुखद जीवन की शुभकामनाएँ!

Translate post

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

@ भरथना

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

इस पुल का भी हाल वैसा जैसे भाजपा सरकार
अटका है अधर में बिना तार, बिना कोई आधार

Translate post

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

बड़ों का तजुर्बा और युवाओं की ऊर्जा मिलकर बनाएँगे
'पॉज़ीटिव इंडिया-स्ट्रॉंग इंडिया'

#Positive_INDIA_Strong_INDIA

Translate post

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

कानपुर स्मार्ट सिटी work of BJP

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

अभी तो बस शुरू हुई है बारिश की कहानी... ग़ाज़ियाबाद से लेकर गोरखपुर तक भाजपा सरकार हुई पानी-पानी!

Translate post

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

जनता कह रही है कि इतने एग्ज़ाम रद्द करने से अच्छा है, ये भाजपा सरकार ही रद्द कर दी जाए।

पंजीकृत डाक पंजीकरण संख्या GPO/LW/NP-300/2024-2026 कुल पृष्ठ : 48 डिस्पैच तिथि : 15, 16, 17

सबकी शान संविधान

समाजवादी पार्टी

/samajwadiparty
www.samajwadiparty.in

QR कोड स्कैन करें और वाट्स-एप चैनल से जुड़ें
/Akhilesh Yadav /Samajwadi Party

हम सबकी शान है संविधान
दलित-बहुजनों की जान है संविधान
भारत देश का गर्व है संविधान

न्याय, समानता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है,
बिना भेद के सबको अवसर, इज्जत और सम्मान देता है,
ऊंच-नीच और छुआछूत के भेद को मिटाता है,
अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना सिखलाया है,

शिक्षा का अधिकार दिलाया है।
इसकी बदौलत...
हम इंसान बन सके,
रोजगार के अवसर मिल सके,
राजनीति के द्वार खुल सके॥

ये है तो हम भी हैं
ये है तो कानून भी है
ये है तो लोकतंत्र भी है
इसलिए, सब शान से बोलो जय संविधान

गर्व से बोलो जय संविधान
दिल में रखो इसे हमेशा
इस पर सदा ही भरोसा

हम सबकी शान है संविधान
दलित-बहुजनों की जान है संविधान
भारत देश का गर्व है संविधान
बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर और संविधान

– सीमा माथुर
(साभार: द शूद्र)